पश्चिम-तटीय रेल परियोजना

*4. **श्री चतुरानन मिश्र :**
डा॰ बापू कालदाते :
क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बम्बई से कन्याकुमारी तक पश्चिमी तट के साथ-साथ रेलवे लाइन का निर्माण किये जाने का किये जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि यह परियोजना पिछले दो वर्षों से रूकी पड़ी है,

(ग) इस परियोजना के लिये कुल कितनी धनराशि निर्धारित की गई है और इस परियोजना का काम कब आरम्भ किया गया था,

(घ) 1988 के वर्ष तक इस पर कितनी धनराशि खर्च की गई,

(ङ) 1988 के वर्ष तक इस पर कितने किलोमीटर लम्बी रेलवे लाईन तैयार कर दी गई थी, और

(च) इस रेल परियोजना का कितना कार्य शेष है?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) जी हाँ ।

(ख) से (ङ) आप्ता और रोहा के बीच 62 किलोमीटर लम्बी वेस्ट कोस्ट रेल परियोजना का चरण-I, 11.19 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 1978-79 में शुरु किया गया था और 24.34 करोड़ रुपये की लागत से मार्च, 1986 में पूरा किया गया था ।

रोहा से मंगलौर तक के सर्वेक्षण को अद्यतन करने का काम 1984-85 में शुरु किया गया था और इसे पूरा करने के बाद नवम्बर, 88 में सर्वेक्षण रिपोर्ट योजना आयोग को भेज दी गयी थी ।

(च) वेस्ट कोस्ट रेल लाइन के शेष 836 कि.मी. भाग पर कार्य किया जाना है ।

---

† सभा में यह प्रश्न श्री चतुरानन मिश्र द्वारा पूछा गया।

श्री चतुरानन मिश्र: सभापति महोदय, वेस्ट कोस्ट लाइन में रेलवे लाइन बिछाने का जो आर्थिक और राजनीतिक महत्व है वह सबके सामने है। उस क्षेत्र के विकास के लिए यह बहुत ही जरूरी है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि 8 साल में इन्होंने 62 किलोमीटर बनवाई। तो यह 832 किलोमीटर की लाइन बनाने में 104 बरस लगेंगे? तो मंत्री महोदय बताएंगे कि 104 बरस को कितना रिड्यूस कर सकेंगे? इसी गति से चलेगा या दूसरी गति होगी? पहला सवाल मेरा यह है।

श्री सभापति: गति के बारे में पूछ रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद: मैं पहले श्री मिश्र जी से यह साफ कहना चाहता हूं कि आप्ता से रोहा तक 62 किलोमीटर हमने बनाया, शेष 836 किलोमीटर जो बाकी है उसके लिए सर्वेक्षण टुकड़ों में किया गया था। टुकड़ा था मंगलोर, मडगांव ...**(व्यवधान...**

श्री चतुरानन मिश्र: हमने यह नहीं पूछा। हमने तो सिम्पल बात पूछी है आपसे सभापति महोदय ...**(व्यवधान)**...

श्री महावीर प्रसाद: माननीय सदस्य महोदय, मैं उसी को स्पष्ट कर रहा हूं जो आपने गति के बारे में पूछा था ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: इतने दिन में आपने इतने किलोमीटर बनाई है, इसी हिसाब से चलेंगे या कुछ तेजी से चलेंगे?

श्री महावीर प्रसाद: श्रीमान्, मैं यही कह रहा था कि गतिशीलता जो है वह योजना आयोग के ऊपर निर्भर करती है। योजना आयोग जितना पैसा हमें देता है उसी के आधार पर हम अपनी गति को तेज करते हैं।

श्री चतुरानन मिश्र: अगर बिना पैसे के मिलता तो हम इनके पास आते ही क्यों? पैसा चाहिए इसीलिए तो सरकार के पास आते हैं। अगर इंजीनियर नहीं चाहिए, मजदूर नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए तो आप किस मर्ज की दवा है? मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आप सदन को आश्वस्त करेंगे कि 8वीं योजना में इसे पूरा करेंगे।

श्री सभापति: वह कोशिश कर रहे हैं कि पैसा मिले। वित्त विभाग से मिलेगा, उसी के अनुसार वह चलेंगे।

श्री चतुरानन मिश्र: सभापति महोदय, मैं पैसे की बात कह रहा हूं। जो 62 किलोमीटर इन्होंने बनाई है उसकी कास्ट दुगनी हो गई थी। 11 करोड़ रुपए थी जो 24 करोड़ रुपए हो गई। तो टाइम फैक्टर होने से कास्ट और बढ़ जाएगा और तब रुपया आपको और भी नहीं

मिलगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस बिन्दु पर आप कहें कि 8वीं योजना में इसे पूरा कर सकेंगे या नहीं?

श्री महावीर प्रसादः महोदय, मैं माननीय विद्वान सदस्य से यह कहना चाहता हूं कि यह मेरी गति की बात नहीं है यह योजना आयोग को चाहिए कि हमारी मदद करे। योजना आयोग हमें संसाधन देगा तो हमें बनाने में कोई कठिनाई नहीं है। जो पैसा हमें मिलता है तो हम एप्रोच करते हैं, कोशिश करते हैं, उसमें गतिशीलता लाते हैं।

श्री चतुरानन मिश्रः योजना आयोग पैसा देता है, उसके अध्यक्ष प्रधान मंत्री जी है, तो क्या दोनों में बातचीत होती है?

श्री सभापतिः वह कह रहे हैं कि प्रयास कर रहे हैं....

श्री चतुरानन मिश्रः इसका जितना महत्व है उसको देखते हुए सरकार क्या इसके लिए योजना आयोग के सामने ऐसी स्कीम देगी कि उसे समय पर पूरा किया जा सके और उसकी लागत न बढ़े?

श्री महावीर प्रसादः श्रीमन मैं पहले ही कह चुका हूं कि हम कोशिश करेंगे। पूरी योजना हमने बनाकर भेज दी है।

डा. बापू कालदातेः सभापति महोदय, मंत्री जी के उत्तर से दो तीन सवाल पैदा होते हैं। एक तो यह कि जब आपने रोहा तक योजना बनाई तब टोटल कोस्ट लाइन के बारे में सर्वेक्षण क्यों नहीं कराया क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि 79 में जनता पार्टी के समय में काम शुरू हुआ और उसके पूरे होते होते 88 आ गया। जिन इलाकों को यह रेल जा रही है उन इलाकों का इससे विकास होगा। लेकिन यात्रा का जो अंतर है वह भी कम होगा। एक ही लाइन पर बोझ डालने के बजाए अगर अल्टरनेटिव रूट हम तैयार करते हैं तो आने जाने की सुविधा भी रहेगी और साथ ही पिछड़े इलाकों का विकास भी होता रहेगा। अगर उसी समय कोस्ट लाइन की बात कर लेते तो शायद कम देर लगती। आपकी साउथ रेलवे की रिपोर्ट के मुताबिक इसको 9 साल लगेंगे। अगर 9 साल लगेंगे तो कास्ट ऐस्केलेशन बहुत हो जाएगी और जिस दाम में हम आज उसको करना चाहते हैं, उसमें वह 9 साल में पूरी नहीं हो सकती। इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बार बार यह कहना कि प्लानिंग कमीशन पैसा देगा तो होगा। प्लानिंग कमीशन आपका है। तो क्या सरकार पिछड़े इलाकों के विकास के लिए तथा यात्रियों के आने जाने का जो अंतर है उसको कम करने की दृष्टि से प्रायोरिटी के रूप में, अग्रक्रम के रूप में इस रेल लाइन के बारे में सोचेगी?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधियां): श्रीमन् पूरी लाइन के सर्वेक्षण की स्वीकृति हमें 1984 में मिली थी। इसीलिए 1985-86 में हमने पूरी लाइन के सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ किया। यह एरिया जैसा माननीय सदस्य जानते है, पहाड़ी इलाका है और काफी दिक्कतों और कठिनाइयों का सामना इस कार्य को पूरा करने में करना पड़ा। इसीलिए 1987 में मंगलौर-उडीपी का जो सर्वे कंप्लीट हो चुका था उसको हमने योजना आयोग के पास भेजा स्वीकृति हेतु। प्लानिंग कमीशन ने हमें उस पर जवाब दिया अप्रैल, 1988 में कि हम मंगलौर-उडीपी लाइन पर अकेले विचार करने के लिए तैयार नहीं है। जब तक पूरा सर्वे हमारे पास नहीं पहुंचे तब तक इसके ऊपर अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सकता। इसलिए हमने पूरे सर्वे पर कार्य तेजी से प्रारंभ किया और जो कार्य चल रहा था उसमें गति पहुंचाई और जुलाई, 1988 में पूरी रेलवे लाइन की सर्वेक्षण रिपोर्ट हमारे पास पहुंची और उसके बाद नवंबर, 1988 में पूरे सर्वेक्षण की रिपोर्ट योजना आयोग के पास पहुंचवाई। योजना आयोग की प्रतिक्रिया इस पर आ चुकी है। उन्होंने हमें यह कहा है कि इसको ऐक्टिवली कंसिडर किया जा सकता है और इस पर बहुत ऐक्टिव कंसिडरेशन चल रहा है और मुझे लगता है कि बहुत शीघ्र इस पर अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा।

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधवः सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि यह जो वैस्ट कास्ट प्रोजेक्ट है वह 8 साल में सिर्फ 62 किलोमीटर कम्पलीट हुआ है। 836 किलोमीटर की लाइन कम्पलीट होती है। मंत्री महोदय ने बताया है यह योजना मंत्रालय का काम है इसलिए कब खत्म होगा हम नहीं कह सकते। मैं यह जानना चाहता हूं....

श्री सभापतिः इन्होंने कहा है कि जल्दी कम्पलीट हो जायेगा। रिपोर्ट दे दी है।

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधवः योजना आयोग से सारे प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा चल रही है। योजना आयोग कभी ग्रीन सिगनल नहीं देता। इसका मतलब यह है कि 8 साल में सिर्फ 62 किलोमीटर की लाइन कम्पलीट हुई है तो 836 किलोमीटर रेलवे लाइन प्रोजेक्ट की ग्रीन सिगनल देने के लिए 30 साल योजना आयोग लेगा। इसका जवाब देने और लेने के लिए जिम्मेदार कौन है? संसद सदस्य हैं, जनता है, सरकार है, रेलवे है

या योजना आयोग है? यह जो जनता की मांग है, जैसा हमारा कोंकिण भाग बहुत सालों से लड़ रहा है कि हम को रेल चाहिए, इसके टाइम बाउंड प्रोग्राम बनाया जाए कि इसके लिए पैसा कैसे उपलब्ध कराया जाए। अगर योजना आयोग से नहीं हो सकता तो मार्किट में बांड सेल किये जायें और पैसा तैयार किया जाये। इससे यह प्रोजेक्ट कम्पलीट कीजिए। इसका समयबद्ध प्रोग्राम इस सदन में रेल मंत्री बताने की कृपा करें।

श्री सभापतिः क्या बांड इसके लिए फ्लोट करेंगे?

श्री माधव राव सिंधियाः ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

डा० बापू कालदातेः जैसे महाराष्ट्र सरकार ने बांड बेचे हैं क्या ऐसी कोई योजना है?

श्री विदठलराव माधवराव जाधवः वैस्ट कास्ट रेल प्रोजेक्ट को कम्पलीट करने के लिए क्या कर रहे हैं यह बताने की कृपा करें।

श्री माधव राव सिंधियाः बांड के बारे में मैंने जवाब दिया कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचारधीन नहीं है।

MR. CHAIRAMAN : Yes, Mr. Hanumanthappa.

SHRI H. HANUMANTHAPPA : Actually, Sir, the Government is completing the Western Ghat Development Programmi: and the Hill Area Development Programme. Will the Railways try to co-ordinate all these programmes ? Without the infrastructure what is the use of the Western Ghat Development Programme or the Hill Area Development Programme. Will they co-ordinate amongst themselves ? If more funds can be provided from the Western Ghat Development Programme or the Hill Area Development Programme to develop the infrastructure, that is, the Konkan railway line, that will also add to the development of the hill areas as well as the Western Ghat area : Will the honourable Railway Minister co-ordinate with' the other Ministries and put it up before the Planning Ministry to get it approved in order to develop the entire Konkan belt ?

SHRI MADHAVRAO SCINDIA : Sir, the Railway Ministry considers this line as a very important line, However, the job of co-ordination Is not within the purview of the activities of the Railway Ministry.- The job of co-ordination is that of the Planning Ministry and the Commission and I would therefore, request the honourable Member to address the suggestion to them.

CHAIRMAN : You can also put forward that suggestion to them.

SHRI MADHAVRAO SCINDIA : We also do it, Sir.

CHAIRMAN : Yes, Mr. Fernandes.

SHRI JOHN F. FERNANDES : Sir, as we all know, Goa lies in the Western Ghat area. I would like to know the length of the railway line passing through the State of Goa and also whether the Goverment will complete the conversion of the MG line into a BG line before this project is taken up.

SHRI MADHAVRAO SCINDIA: Sir, the proposed alignment does pass through the State of Goa. But I cannot give the exact kilometreage which passes through the State of Goa. But, actually, it goes from the south to the north or from the north. to the south whichever way you (look at it. It goes through the length and-breadth of Goa, from one end to tho other.

MR. CHAIRMAN : Yes, Mr. Kunjachen.

SHRI JOHN F. FERNANDES : Sir, he has not answered the second part of my question...'*(Interruptions).*

SHRI MADHAVRAO SCINDIA : Sir, it passes through the length of Goa and not breadth.

SHRI P.K. KUNJACHEN : Sir, when the Government reviewed certain projects, it was found that no time had been

fixed for finishing the projects and, as such, the price escalation was twice or thrice the original estimate. Therefore, considering this factor, will the Government fix a time for the completion of this line ?

SHRI MADHAVRAO SCIND1A : Sir," the progress on the line will naturally be commensurate with the funds provided, the allocations that are made.

SHRI P.K. KUNJACHEN : Sir, I wanted to know whether they will fix the time for the completion of this project, It takes a number of years for finishing the project. So, this is my question. Are you prepared to fix a time, number of years for completing the project ?

SHRI MADHAVRAO SCINDIA : This is a very vast project and it will proceed according to the funds provided. I cannot give any commitment as far as the completion of the project is concerned.

MR. CHAIRAMAN : The Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Extension of Broad Guagc RaUwr-*Uat* from Guwahatl to Dibrugarh

'2 SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether there is any tresh proposal mder Government's consideration for the xtension of broad-gauge railway line rom Guwahati to Dibrugarh during the 988-90 annual plan; and

(b) if so by when the proposal for the Ktension of broadgauge line is likely to e taken up ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI IAHABIR PRASAD): (a) No, Sir,

(b) Does not arise.

Acquistion of Aircraft from USSR

*5 KUMARI SUSHILA TIRIA : SHRI MAHENDRA PRASAD :

Will the Minister of CIVIL AVIATION AND TOURISM be pleased to state :

(a), how many Soviet aircraft are being procured on lease for Air India, Indian Airlines and Vayudoot and of what make and at what cost;

(b) whether joint Indo-Soviet produc tion of commercial jets is also proposed; if so, what are the details thereof;

(c) whether Soviet pilots would also be inducted along with their aircraft and whether there has been any protest by Indian pilots; if so, on what grounds; and

(d) whether Indian Airlines is starting joint services with Aeroflot to Moscow or Tashkent by flying leased Soviet aircraft; and if so, what are the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION AND TOURISM (SHRI SHIVRAJ ... PATIL);(a) Indian Airlines have a proposal to procure two Soviet aircraft on wetlease :—

(i) TU-154 at lease charge of Rs. 80,000 per flying hour and (ii) 1L-62M aircraft at loase charge of • Rs. 70,000 per flying hour.

There is no proposal to take Soviet aircraft on lease for VrfjMdoot. Air India is already using one IL-62M Aircraft of Aeroflot taken on wetlease at a charge of 3,000 Roubles per flying hour and one IL-76 aircraft for freighter flights under the Aeroflot/Air India Charter arrengements at a lease charge per flight which varies from Rs. 2.94 lakhs to Rs. 3.60 iakhs depending on the route operated.